केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 4 जुलाई को संसद में 2018-19 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की।

आर्थिक समीक्षा क्या होती है?- आर्थिक समीक्षा, आम तौर पर बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। इसमें पिछले एक साल में देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का लेखा-जोखा और मुख्य विकास कार्यक्रमों का सार दिया जाता है। इसके अलावा यह सर्वेक्षण भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए भी एक दृष्टिकोण का काम करता है।

आर्थिक समीक्षा 2018-19 के मुख्य बिन्दु :-

- वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2018-19 में 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2025 तक भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रति वर्ष 8% की दर से GDP वृद्धि की आवश्यकता है।
- पिछले 5 वर्षों वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चालू खाता घाटा काबू करने लायक स्तर पर बना रहा तथा विदेशी मुद्रा भंडार अब तक सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है। 2018 में वृद्धि दर के मामले में चीन को पीछे कर दिया है।
- 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 3.4% रहने का अनुमान है। देश में अनाज उत्पादन 28 करोड़ 34 लाख टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में आयात 16.4% की दर से बढ़ेगा, जबकि निर्यात की वृद्धि दर 12% 12.5 प्रतिशत रहेगी। राजकोषीय वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार 41 खरब 29 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

MPPSC UPSC
MPSI IAS IPS
Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station, Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001

• भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2021-31 के दौरान 1 प्रतिशत से कम और 2031-41 के दौरान 0.5 प्रतिशत से नीचे रहेगी। जनसंख्या में 0-19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 2011 के उच्चतम स्तर 41 प्रतिशत से घटकर 2041 में 25% रह जाएगी। आबादी में 60 वर्ष आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 2011 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2041 तक 16% पर पहुँच जाएगी। सेवानिवृत्ति की उम्र चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की बात भी कही गई है।

• मार्च, 2018 और दिसंबर, 2018 के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 11.5% से घटकर 10.1% हो गया।

अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों का संचालन निजी कंपनियों को देने का फैसला

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत लीज पर देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले अडानी इंटरप्राइजेस को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। अभी इन हवाई अड्डों का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के पास है। इन तीनों हवाई अड्डों से AAI को जितनी आमदनी होती है, लीज पर देने से उसकी 10 गुना राशि एकमुश्त मिल जाएगी। इसके अलावा निजी संचालकों को होने वाले मुनाफे में भी उसकी हिस्सेदारी होगी।

बिरला समूह के संरक्षक बीके बिरला का निधन

बिरला समूह के संरक्षक बीके बिरला का 3 जुलाई को मुंबई में निधन हो गया। वे 98 साल के थे। वे सेंचुरी टेक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे।

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station, Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001

फर्राटा धाविका हिमा दास ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रैं प्री में स्वर्ण पदक जीता

भारत की फर्राटा धाविका हिमा दास ने 4 जुलाई को पोजनान एथलेटिक्स ग्रैं प्री प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता पोलैंड में आयोजित की गई थी। हिमा ने 200 मीटर दौड़ 23.65 सेकंड में पूरा कर यह पदक अपने नाम किया।

इसी प्रतियोगिता में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रेकॉर्डधारक तजिंदर पाल सिंह तूर ने कांस्य पदक हासिल किया। एशियाई चैंपियन तूर ने पुरुषों के गोला फेंक में 19.62 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। मोहम्मद अनस पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में और केएस जीवन ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।

वर्ष 2019-20 के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गयी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने वर्ष 2019-20 के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को 3 जुलाई को मंजूरी दे दी।

क्या है एमएसपी- एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है। सरकार हर साल फसलों की एमएसपी तय करती है ताकि किसानों की उपज का वाजिब भाव मिल सके। इसके तहत सरकार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड जैसी सरकारी एजेंसियों की मदद से किसानों की फसलों को खरीदती है।

By- Pankaj Bodiya

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station,
Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001